SHRI KEDAR PANDAY : I have followed. The Hon. Member referred to the setting up a Tribunal under the present existing constitution. I don't think it is necessary just now unless we have had a full discussion with these State Governments. So far we have not made up our mind to settle this matter through Tribunal. We shall try to negotiate failing which we shall think of what should be done.

National Water Plans

*604. SHRIMATI USHA PRAKASH CHOUDHARI : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether during the present year of productivity Government propose to devise national water plan :

(b) whether it is also proposed to provide higher outlays, full utilisation of funds, adequate power and diesel to run the tubewells and preservation of ecological factors ; and

(c) what other action Government propose to take to remove inefficiencies in the present water resources development in India ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI Z. R. ANSARI) : (a) to (c). During the current productivity year, special efforts are being made to achieve additional agricultural production by taking the following actions so far as Irrigation Ministry is concerned —

(i) ensuring quicker and more efficient utilisation of irrigation potential by construction of field channels upto the last field ;

(ii) introduction of warabandi (rotational water supply) ; and

(iii) during 1982-83, an outlay of nearly Rs. 2100 crores has been provided including command area development but excluding institutional finance. The corresponding figure for 1981-82 was Rs. 1830 crores. For major irrigation projects, the physical and financial progress is being monitored within the State as well as by the Central Government so as to ensure not only fuller utilisation but more efficient use of funds so that the benefits accrue at the earliest. Measures are being taken to improve the power supply. The supply position of diesel has been generally satisfactory, so far as the pumpsets are concerned. The programme of energisation of pumpsets is also being accelerated.

More funds are being provided for on-going projects so as to complete them as early as possible. Provision of drainage and conjunctive use of ground and surface water are proposed to counteract water logging conditions.

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस समय जो हालात जल-योजना के हैं या जो उन कार्यों का स्वरूप है, उन से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा । हम ने बीस सूत्री कार्यक्रम में भी इस प्रोग्राम को काफी महत्व दिया है । इसलिये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि हमारे देश में जो जल के प्राकृतिक साधन बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं—ऊंचे पर्वत हैं तथा बड़ी नदियां हैं, उन के सहारे या अन्य मार्गों से देश के पानी का पूरा उपयोग करने के लिये आप कौन सी विशेष योजनाएं बनाने जा रहे हैं ? क्या इस के लिये कोई निश्चित प्लान आप के विचाराधीन हैं ?

मैं यह भी जानना चाहती हूं—साइन्स तथा टैक्नालाजी डिपार्टमेन्ट की ओर से एक

एक्सपर्ट बनाया गया था और उन्होंने जो राय दी है उस के मुताबिक हम लोगों को लांग ड्यूरेशन के प्लान बनाने चाहिये तभी इस देश में जल-पूर्ति कर सकते हैं। इस के बारे में शासन क्या विचार कर रहा है ?

श्री मूल चन्द डागा : राजस्थान कैनाल बनाइये।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जहां तक प्रोडक्टिविटी ईयर के अन्दर इरीगेशन पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए और उस के यूटीलाइनशन के लिए इर्रीगेशन मिनिस्ट्री को जो स्टेप्स लेने चाहिए, उन का सवाल है, उस के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस हद तक हम उस को पूरा कर सकते हैं और उस के लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए, वे हम ने इस जवाब में पूरे तौर पर आइडेंटीफाई कर दिये हैं।

अब जहां तक सांइस एण्ड टैक्नोलोजी की किसी कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है, जिस का हवाला माननीय सदस्या ने दिया है, मेरी इस वक्त उस के बारे में वाकफियत नहीं है, जिस से मैं उस के सिलसिले में जवाब दे सकूं।

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आप ने जवाब में बताया है कि 1982-83 के लिए 2100 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है लेकिन उस की परिपूर्ति के लिए आप ने कोई निश्चित रूपरेखा सामने नहीं रखी। मैं यह पूछना चाहती थी कि नई व्यवस्था का फायदा कितने हैक्टेयर को मिल सकता है और इस में से स्टेटवाइज अन्दाजन कितना रुपया आप स्टेटेवाइज खर्च करेंगे। यह भी महत्वपूर्ण है कि एक बैलेंस इस में रखना चाहिए। इसलिए मैं यह जानना चाहती हूं कि 1980-81 और 1981-82 का जो प्लान आप ने बनाया था, उस में जो धन-राशि खर्च हुई है, उस का अचीवमैंट क्या है ? हमने क्या पाया और हम क्या करने जा रहे हैं और नये प्लान में क्या इस का ध्यान रखा जाएगा।

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : माननीय सदस्या ने जो सवाल पूछा है, उस के मुताल्लिक मुझे यह कहना है कि 1982-83 में हम 3 मिलियन हैक्टेयर में इर्रीगेशन पोटेंशियल क्रीयेट करना चाहते हैं और छठी पंचसाला प्लान के खत्म होते वक्त, 14 मिलियन हेक्टेयर का मेरा लक्ष्य है। इतना इर्रीगेशन पौटेंशियल मैं इस देश में क्रियेट करूंगा और ये जो तीन साल बाकी हैं छठी पंचसाला प्लान के, हर साल हम 3 मिलियन हैक्टेयर इर्रीगेशन पौटेंशियल क्रीयेट करना चाहते हैं और अभी तक जो इर्रीगेशन पौटेंशियल सारे देश में है, टोटल, वह करीब 60 मिलियन हेक्टेयर है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 14 नहीं हुआ।

श्री केदार पांडे : 14 में से 5 हो गया और 9 में से 3, 3 करेंगे हर साल, इस में आप संदेह न कीजिए। यह पहली बात है। इसी लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि 1981-82 में अभी तक जो इर्रीगेशन पोटेंशियल सारे देश में पैदा हुआ है, वह मेजर इर्रीगेशन, मीडियम इर्रीगेशन और माइनर इर्रीगेशन सब मिला कर करीब-करीब 60 मिलियन हैक्टेयर हो चुका है और उस में से 54 मिलियन हैक्टेयर युटीलाइज हो गया है। इसलिए 6 मिलियन हैक्टेयर यह रहा और 3 मिलियन हैक्टेयर 1982-83 में, प्रोडक्टिविटी इयर है, हम क्रीयेट करना चाहते हैं। यही मेरा नकशा है और इस नक्शे के मुताबिक हम

चाहते हैं कि 1982-83 का जो हमारा प्रोडक्टिविटी इयर है, उस में कम से कम 4 मिलियन टन अनाज ज्यादा पैदा करें। आज जो पैदा होता है, उस से इतना ज्यादा पैदा करें। अब जितनी पैदावार हिन्दुस्तान में होती है, वह 60 मिलियन टन के करीब है और उस का 60 परसेन्ट इर्रीगेटेड एरियाज में अनाज पैदा होता है। इसलिए इर्रीगेशन को अगर हम बढ़ाएंगे और 1982-83, जो प्रोडक्टिविटी इयर का एलान हुआ है, में अगर हम एफेर्ट करेंगे, तो हमारा प्रोडक्शन बढेगा। हमारे नये बीस-सूत्री प्रोग्राम में यह पहला प्वाइन्ट है और इस देश में हमें इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। इस से देश आगे बढ़ेगा, बनेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगी।

श्री सतीश अग्रवाल : माननीय सिंचाई मंत्री ने जो अभी सदन में घोषणा की है, इसी प्रकार की घोषणा सन् 1951 में, जब प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी थी, उस समय की गई थी और उस घोषणा के अनुसार इन पिछले 30 वर्षों में मेजर और मीडियम इर्रीगेशन का जो लक्ष्य रखा गया था, वह 30 मिलियन हैक्टैयर का था और उस में से उपलब्धि हुई है 18 मिलियन हैक्टेयर और उस में से जो वास्तविक उपयोग हो रहा है, वह है 12 मिलियन हैक्टेयर। जितने टार्गेट थे 30 वर्षों में, उस के लिए आप ने 10009 करोड़ रुपये खर्च किये और उपलब्धि हुई 60 परसेन्ट और यूटीलाइजेशन है 40 परसेन्ट। अब 6 मिलियन हैक्टेयर की आप बात कह रहे हैं। ये गलत आंकड़े हैं, मैं इस में से माइनर इर्रीगेशन को हटा कर बात कर रहा हूं। माइनर में तो छोटे छोटे तालाब राजस्थान में बन जाते हैं। समस्या है तो नागार्जुनसागर की, समस्या है कोशी की, समस्या है राजस्थान नहर की। अध्यक्ष महोदय, आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि इन सारी 8 सिंचाई योजनाओं को पिछले तीस वर्षों में पूरा नहीं किया जा सका है। इन सारी योजनाओं पर 10 हजार 9 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। 1951 से 1981 तक तीस वर्षों में 30 मिलियन हैक्टर का हमारा लक्ष्य था, 18 मीलियन हैक्टेयर हमने अचीव किया और 12 मिलियन हैक्टेयर की आपकी उपलब्धि है। इस प्रकार की घोषणाएं कर के आप सदन को और जनता को धोखे में न रखें। सिंचाई ऐसी चीज है जो कि किसानों, और पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न के ऊपर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। हमारा इम्प्लीमेंटेशन बहुत फाल्टी है। इसका कारण यह है कि हमारे प्रोजेक्ट्स की कास्ट रनओवर और टाइम रनओवर बहुत ज्यादा है। आप इन आंकड़ों के सम्बन्ध में बताइये और जो मैंने बात कही है उसके सम्बन्ध में बताइये।

श्री केदार पांडे : इस देश में मेजर, मीडियम, माइनर इर्रीगेशन और ग्राउन्ड वाटर सब मिला कर 113 मिलियन हैक्टर आता है। जो आपने पहली कहानी कही है, उस से ऐसा लगता है कि आप उदास हैं। आपको आज की कहानी सुन कर खुशी होगी। आप पहली कहानी की बात करते हैं। उस वक्त मुमेन्टम नहीं आया था। जो मुमेन्टम आज आया है, उसके फैक्ट्स एण्ड फिगर्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये बनावटी फिगर्स नहीं हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : जो कहानी आपके अधिकारियों ने मुझे बतायी है, वही मैं कह रहा हूं।

श्री केदार पांडे : आज की कहानी से आप फ्रस्ट्रेटिड नहीं बनेंगे, उससे आप ओप-

टीमिस्टक हो जाएंगे । आप पहले की बात नहीं रखें । हमारा अल्टीमेट इर्रीगेशन पौटेंशियल इनक्लूडिंग ग्राउंड वाटर 113 मिलियन हेक्टेयर इर्रीगेशन पौटेंशियल है । उसको हमको अचीव करना है, क्रियेट करना है । अभी तक हम 60 मिलियन हेक्टेयर क्रियेट कर सके हैं इन्क्लूडिंग आल दिस । उस में से 54 मीलियन हेक्टेयर यूटिलाइज्ड है । आई एम टार्किंग आफ फिगर्स । आप देख लीजिए । अगर आप मेरे फिगर्स को चैलेंज करते हैं तो आप दूसरे फिगर्स दीजिए । ये जो मैं फिगर्स दे रहा हूं ये चारों तरफ से जांच कर के दे रहा हूं। 60 मिलियन हेक्टेयर देश में क्रियेटिड है जिसमें से 6 मिलियन हेक्टेयर कम यूटिलाइज्जड हैं। हमने 54 मिलियन हेक्टेयर यूटिलाइज किया है । इसी वजह से अनाज की पैदावार बढ़ी है । इर्रीगेटिड एरियाज में पैदावार ज्यादा बढ़ जाता है । आई एम नाट टार्किंग इन द एयर, आई एम टार्किंग आन द ग्राउण्ड हमारी मेजर इर्रीगेशन पोटेंशल 28.5 मिलियन हेक्टेयर का क्रियेट हुआ है जिसमें से चार मिलियन हेक्टेअर अनयूटिलाइज्ड है । उसको हम इस साल में करना चाहता है। हम तीन मीलियन हेक्टेअर का आगे बढ़ा देंगे । इस तरह हम तीस मिलियन हेक्टेअर कुल मिला कर देंगे । हम आगे बढ़ेंगे । यह है आज की हमारी तस्वीर ।

जो मैं घोषणा करता हूं उसका बेसिस है, उसका आधार है । निराधार बात मैं नहीं करता । जो बात आप करें वह फैक्ट्स एण्ड फिगर्स के साथ बात करें। मैं आप से कहना चाहता हूँ कि मैं मैथेमैटिक्स का विद्यार्थी हूँ। आप हैं या नहीं हैं, यह मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं तो फैक्ट्स एण्ड फिगर्स के साथ बातें करता हूं । आप अगर ये न मानें तो दूसरे फिगर्स इनके खिलाफ दीजिए । आप फ्रस्ट्रेटिड हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने प्रमाणित किया है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : कहानी तो कहानी ही रह जाएगी, पूरी बात नहीं होगी । (**व्यवधान**)

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है :—

"During the current productivity year, special efforts are being made to achieve additional agricultural production by taking the following steps . ..."

इसमें एक-दो-तीन कर के कहा है—

इन्होंने कहा है कि—

ensuring quicker and more efficient utilistion of irrigation potential by construction of field channels.

मैं खासकर बिहार के कोसी क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं, जहां से मैं आता हूं । वहां पूर्वी तटबन्ध पूरा हो गया है, जिससे सिंचाई होती है ।

अध्यक्ष महोदय : आप कोसी से आते हैं, मैं पंचकोसी से आता हूँ ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि पूर्वी तटबन्ध पूरा होने के बावजूद भी पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा आदि इलाकों में फील्ड चैनल्स के बिना सिंचाई नहीं हो पा रही है । दूसरी बात क्या मन्त्री महोदय को इसकी भी जानकारी है कि पश्चिमी तटबन्ध अभी तक पूरा नहीं हुआ है । यह कब तक पूरा हो जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल इसके अन्तर्गत नहीं आएगा ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : तीसरी बात भारत सरकार कमाण्ड एरिया पर भी कुछ पैसा खर्च करना चाहती है । क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि कोसी कमाण्ड एरिया में जहां कोसी से सिचाई नहीं हो सकती साथ ही दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं हो सकती । इस ऐनामली को दूर करने का क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्री केदार पाण्डे : वाकई यह सवाल सम्बन्धित नहीं है, लेकिन मैं इसको इवेड नहीं करना चाहता, क्योंकि बिहार की बात है और मैं बिहार का रहने वाला हूं ।

वेस्टर्न कोसी केनाल 1987 में पूरी होगी, ईस्टर्न कोसी कैनाल बहुत कुछ पूरी हो चुकी है और 1983 तक इसका पूरा काम हो जाएगा । वैस्टर्न कोसी कैनाल अभी हिन्दुस्तान में पूरी नहीं बनी है, ज्यादा नेपाल टेरीटरी में बनी है ।

श्री राम विनास पासवान : हिन्दुस्तान में क्यों नहीं बनी ?

श्री केदार पांडे : पहले नेपाल से आएगी तभी तो हिन्दुस्तान में बनेगी ।

श्री राम विलास पासवान : एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ—अगेंस्ट ललित नारायण मिश्र ? (व्यवधान)

श्री केदार पांडे : आप लोग इसमें कोई शंका न करें, 1987 तक काम कम्प्लीट हो जाएगा । काम लगा हुआ है ।

तीसरी बात कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट के बारे में है । अभी भी बहुत जगह इरीगेशन पोटेंशियल क्रिएट करते हैं । पानी यूटीलाइज करने के लिए नहर से खेत तक ले जाना होता है और उसके मुताबिक फील्ड चैनल्स बनाने हैं । कुछ बनाए हैं, कुछ काम बाकी है । मैं माननीय सदस्य की इस बात से भी सहमत हूं कि काम में कुछ सुस्ती हुई है । मैं स्वभाव के मुताबिक कोई बात छुपाता नहीं हूं ।

श्री राम विलास पासवान : आप छिपा रहे हैं—एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ (व्यवधान)

श्री केदार पाण्डे : फील्ड चैनल्स बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा एक्स्पीडाइट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कदम उठा रहे हैं । इसके लिए हमारे पास पैसा भी काफी है । 2100 करोड़ इस साल इर्रीगेशन के लिए है । इस कार्य पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की कोशिश करेंगे । कोसी कैनाल के बारे में मैं भी सीरियस हूं और चाहता हूं कि काम ठीक होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप डण्डा घुमाकर काम भी जल्दी करवा दीजिए ।

SHRI BHERAVADAN K. GADHAVI : Sir, you will agree that ever since we become independent, our Government has been paying special attention to agriculture. Still it cannot be denied that our agriculture has not ceased to be a gamble on the rain. Of course, throughout, all the Prime Ministers have emphasised that agriculture and irrigation potential should be increased. There is no doubt about it. But as Shri Satishji said, there is some slippage in some of the major projects because of the inter-State disputes and other constraints and impediments that are not solved or removed as expeditiously as we

want to get them through. And, therefore, there was also a statement made by our Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi that irrigation should be brought under Central List, so that all these inter-state disputes which arise, and which put impediments in the process of implementation, can be removed. Since this Council has been set up, I would like to know whether Government is seriously thinking, as a matter of policy, of putting irregation exclusively in the Central List, so that all these disputes which come in the way of irrigation projects, can be settled very expeditiously.

SHRI Z.R. ANSARI : At present there is no proposal to bring irrigation under Central List.

मध्य प्रदेश का विदेशी सहयोग के साथ मत्स्य पालन विकास का प्रस्ताव

605. **श्री केयूर भूषण :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने डेनमार्क सरकार से मत्स्य पालन विकास के लिए प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के कौन-कौन से जिले लिए जायेंगे ;

(ग) क्या डेनमार्क सरकार ने योजना को अपनी मंजूरी दे दी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो यह योजना कब तक हाथ में ले ली जायेगी ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN) : (a) Yes, Sir.

(b) 1. Gawalior
2. Datia
3. Morena
4. Bhind
5. Shivpuri
6. Guna
7. Tikamgarh
8. Sagar
9. Chhatarpur
10. Hoshangabad
11. Raisen
12. Bhopal
13. Sehore
14. Mandsaur

(c) and (d). Proposal is under consideration of the Government of Denmark.

श्री केयूर भूषण : कब इस योजना को आप ले रहे हैं और कब यह पूरी होगी ? मत्स्य पालन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। रोजगार की दृष्टि से सर्वसाधारण तक पहुंचने के लिए यह अनाज से भी ज्यादा महत्व की है। जहां पर काम यह चल रहा है वहां अन्तर्प्रदेशीय मत्स्य परियोजना के सात जिले क्रमशः शिवपुरी, दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर तथा राजनन्दगांव लिए गए हैं। वहां जो मछली पालन का काम हो रहा है, उसका लाभ नीचे के लोगों को मिल नहीं पाता, बीच के बिचौलिये उसको ले जाते हैं। विचौलिये यह लाभ न कमा पाएं और सीधे नीचे के लोगों को, आदिवासियों, हरिजनों और गरीबों को ही लाभ मिल सके, इसके वास्ते आपके पास कोई योजना है ? ऐसी कोई योजना है कि जो छोटे-छोटे किसान हैं वे भी इसको लागू कर सकें, जिन के पास पांच सात एकड़ जमीन है और उस में से एक या आधा एकड़ में तालाब बना सकें और मत्स्य पालन कर सकें, उसके वास्ते कुछ विशेष सुविधा देने की आपके पास कोई योजना है ?